



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 1973/भाद्र 9, 1895

No. 298]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1973/BHADRA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st August 1973

S.O. 455(E)/18FB/IDRA/73.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 678/18A/IDRA/72, dated the 24th October, 1972, the management of the industrial undertaking known as Messrs. Carter Pooler and Company Pvt. Ltd., Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 23rd October, 1977;

An whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking is party or which may be applicable to such industrial undertaking immediately before the date of issue of this order and all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder, before the said date shall remain suspended for a period of one year.

[No. F. 1/92/71-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1973

एस०ओ० 455(अ०)/18वल्/आई० डी० आर० ए०/73.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का० आ० 678/18ए/आई० डी० आर० ए०/72 विनांक 24 अक्तूबर, 1972 द्वारा मैसर्स कार्टर पुलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से शाल औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन पांच वर्ष की अवधि तक और जिसमें 23-10-1977 भी सम्मिलित है ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बारे में जन साधारण के हित में अनुसूचित उद्योग के उत्पादन के परिणाम में कमी को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 18ब, ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि किसी अथवा सभी संविदाओं संपत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, समझौतों/पंचाटों, स्थायी आदेशों अथवा अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका कि उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को इस आदेश के जारी होने के तत्काल पूर्व लागू है, और तद्धीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाली सभी अथवा कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व, उक्त तारीख के पूर्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[सं० फा० 1/92/71-सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।